केंद्रीय बैंकिंग और अकादमी *

या.वे. रेड्डी

महामहिम कुलपति, सर रमेश जीवूलाल, माननीय प्र. कुलपति प्रोफेसर जुगेसर, माननीय उप कुलपति, प्रोफेसर फगूनी, गवर्नर भीनिक, सम्मानित विद्वज्जन और मित्रो, मारीशस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्राप्त करना बड़े सम्मान और गौरव की बात है। मैं इस सम्मान के लिए बैंक ऑफ मारीशस के गवर्नर तथा अवैतनिक प्रोफेसर रंधीर सिंह भीनिक की हृदय से प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यह एक विशेष महत्व का अवसर है क्योंकि इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और इसने महाद्वीपों में स्थित वैश्विक रूप से प्रख्यात कई शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारत एक सुविख्यात उदाहरण है। इस विश्वविद्यालय के प्रति भारत में बड़ा सम्मान है जैसा कि एक चर्चा प्रधान सत्र के लिए भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा इस विश्वविद्यालय में किए गए दौरे से स्पष्ट है। यह सत्र विश्वविद्यालय के इस सभागृह में 13 मार्च 2006 को आयोजित किया गया था।

मुझे यह उपाधि देने से मारीशस और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। यह हमारी आपसी इच्छा का भी संकेत है कि उन क्षेत्रों में हमारे संबंध सुधरें और मजबूत हों, जो तेजी से विकासमान विश्व के लिए आवश्यक हैं जैसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र और पर्यटन। यह अच्छी बात है कि प्रोफेसर

* 3 दिसंबर 2007 को मारीशस में, मारीशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि प्रदान करने के अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ.या.वे.रेड्डी द्वारा दिया गया भाषण।

फगूनी ने सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और पर्यावरण में हाल में रुचि दिखाई है। प्रसंगवश, इस विषय पर केंद्रीय बैंकों और शिक्षाविदों के बीच चर्चा आयोजित की जानी चाहिए।

यह सुज्ञात है कि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवहार को इस विषय पर शैक्षिक अंशदान से काफी कुछ मिलता है। सैद्धांतिक नींव के अलावा, शिक्षाविद्, सहयोगात्मक कार्य में अनुसंधान इनपुट के अनुसार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता के अनुसार नीति संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जबकि शिक्षाविदों को प्रायः केंद्रीय बैंकों के बोर्ड अथवा समितियों में रखा जाता है, यह भी कोई असामान्य बात नहीं है कि गवर्नरों को शिक्षाविदों के बीच से लिया जा जाता है, हाल के कुछ सुज्ञात उदाहरण हैं - संयुक्त राज्य अमरीका के प्रोफेसर बेन बेर्नां के, बिट्रेन के मेर्विन किंग, जर्मनी के एक्सेल वेबर, इजराइल के स्टेंले फिशर और यहाँ उपस्थित मारीशस के प्रोफेसर भीनिक। नि:संदेह, केंद्रीय बैंक शैक्षिक और अन्य अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करता है। प्रायः, केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रयासों को, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र को, महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है।

हमारा रिज़र्व बैंक शिक्षाविदों के साथ कई तरीके से चर्चाएं करने को बहुत अधिक महत्व प्रदान करता है। भारत में 1990 के दशक के प्रारंभ में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की नींव एक शिक्षाविद गवर्नर श्री रंगराजन द्वारा रखी गई थी, जो मूल रूप से भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर के पद से लिए गए थे।

रिज़र्व बैंक के बोर्ड में सामान्य रूप से चार लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होते हैं - दो अर्थशास्त्र से और दो विज्ञान से।

निरंतर रूप से, रिज़र्व बैंक को शिक्षाविदों से प्राप्त सक्रिय इन्पुट से लाभ मिलता है। मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजार और आवधिक सर्वेक्षणों की हमारी स्थायी तकनीकी परामर्शदात्री समितियों में शिक्षाविदों के होने के बहुत अधिक लाभ मिलता है।

रिज़र्व बैंक अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए अपने प्रमुख विश्लेषणात्मक प्रकाशनों जैसे - वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, राज्य वित्त : बजटों का अध्ययन, समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियाँ, साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक, मासिक बुलेटिन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंड बुक के माध्यम से शैक्षिक जगत की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

रिज़र्व बैंक डेटाबेस आन इंडियन इकनॉमी (डीबीआइई) के माध्यम से अनुसंधानकर्ताओं को वेब आधारित पहुँच प्रदान करता है। वित्तीय क्षेत्र, संपदा क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय बाजार, सार्वजनिक वित्त और कंपनी वित्त के क्षेत्र से संबंधित समय श्रृंखला के आंकड़े डीबीआइई के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। प्रयोगकर्ता मेटा डाटा से संबंधित आंकड़ों/रिपोर्टो तक जा सकते हैं। वे आंकड़ों/रिपोर्टो से संबंधित मेटाडाटा तक भी जा सकते हैं।

अन्य बड़े केंद्रीय बैंकों की तरह, रिज़र्व बैंक ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के क्षेत्र में अपनी अनुसंधान क्षमता को विकसित किया है जिससे अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को बेहतर रुप में समझने में सहायता मिलती है।

बहुविषयक दृष्टिकोण से विकास के मामलों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, 1986 में रिज़र्व बैंक द्वारा एक उन्नत अनुसंधान संस्थान इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आइजीआइडीआर) की स्थापना की गई। आइजीआइडीआर को रिज़र्व बैंक से वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है। इस संस्थान को अब माने गए विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई है।

1991 में रिज़र्व बैंक द्वारा बनाया गया विकास अनुसंधान समूह व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों और बैंक के अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। विकास अनुसंधान समूह ने अपनी शुरुआत से संपदा और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषयों पर व्यापक रूप से 25 अध्ययन प्रकाशित किए हैं। इन अध्ययनों को रिज़र्व बैंक द्वारा निधि प्रदान की गई है।

रिज़र्व बैंक ने 1969 में एक स्वायत्त शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआइबीएम) की स्थापना की थी जिसे बैंकिंग प्रणाली के "विशेषज्ञ दल (थिंक टैंक)" की सक्रिय भूमिका अदा करने का अधिदेश दिया गया। एनआइबीएम को स्नातकोत्तर अनुसंधान के लिए अनुमोदित केंद्र के रूप में पुणे विश्वविद्यालय द्वारा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। हाल में पुणे में एनआइबीएम कैम्पस में संयुक्त भारत-अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। रिज़र्व बैंक ने इस सहयोग को प्रायोजित किया है और इसके लिए निधि प्रदान की है। यह विश्व में आइएमएफ संस्थान की सातवीं ऐसी सुविधा है।

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर और वर्तमान प्रधानमंत्री, प्रोफेसर मनमोहन सिंह ने हाल में किए गए रिज़र्व बैंक के दौरे के समय 50 वर्ष पुराने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय का उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र के रूप में उन्नयन करने के लिए उद्घाटन किया। यह अध्ययन केंद्र उच्च अधिकार- प्राप्त परामर्शदात्री समूह की मदद से अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है।

रिज़र्व बैंक विभिन्न संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के रुचि के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण देने के लिए रिज़र्व बैंक की धर्मादा (इंडोमेंट) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है। वित्तीय सहायता सामान्य रूप से कार्पस निधियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। वर्तमान में, 21 कार्पस निधियां हैं और लाभ लेने वालों में कई विश्वविद्यालय हैं।

रिज़र्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा दिए जाने वाले अनेक सेमिनारों/भाषणों को धन प्रदान करता है जिसमें से प्रमुख तीन स्मारक व्याख्यानों की सर्वाधिक उल्लेखनीय श्रृंखला और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक कार्यशालाओं/सम्मेलनों को दी जाने वाली सहायता शामिल है।

इस प्रक्रिया की निरंतरता के रूप में और क्षमता निर्माण तथा ज्ञान प्रबंधन संबंधी पहलों के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने एलएसई इंडिया ओब्जरवेटरी और आईजी पटेल पीठ के निर्माण के लिए, प्रवर्तकों में से एक के रूप में हाल में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पालिटिकल साइंस (एलएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, प्रमुख अर्थशास्त्री लार्ड निक स्टर्न सभापति हैं। एलएसई इंडिया ओब्जरवेटरी एलएसई में भारत से संबंधित अनुसंधानों, नीतिगत गतिविधियों और शिक्षण को समन्वित करती है और इसके भारत के शैक्षिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और कंपनी निकायों के साथ शैक्षिक सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में उभरने की आशा है।

हमारा विश्वास है कि यह अवसर हमारे दो देशों, अर्थव्यवस्थाओं, वित्तीय क्षेत्रों, केंद्रीय बैंकों और शिक्षाविदों के बीच और अधिक सहयोग के लिए हमारी साझी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।